डॉ. हरिहर प्रसाद सिंह व अन्य

बनाम

प्रिन्सिपल एमएलएन मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद और अन्य

21 अगस्त 1990

[एस. रंगनाथन और के.एन. साईकिया, जे. जे.]

व्यावसायिक महाविद्यालय- इनमें प्रवेश:- रेजिडेन्सी स्कीम- खण्ड 5- मोतीलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज- पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश- यू. एस.समय का निर्वचन पैरा अपीलकर्ता कनिष्ठ चिकित्सक है जो 22.08.1989 पर हाउस जॉब कर रहे थे, जिन्हें जूनियर डॉक्टरों के लिये 'रेजिडेन्सी स्कीम' के तहत एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज में स्नातकोतर डिग्री पाठयक्रम द्वितीय वर्ष में प्रवेश कराया गया था, जिसे 22.08.1989 पर अधिसूचित किया गया था, लेकिन 1.08.1987 से भूतलती प्रभाव दिया गया था। हालांकि, वे उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरुप अपनी सीटें खो बैठे, जिसमें प्रतिवादी-डॉक्टरों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई, जिनके उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदन खारिज कर दिये गये थे।

निवास योजना द्वारा शुरु किये गए संशोधनों के लिए दो उद्देश्यों के लिए कुछ अस्थायी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता थी। सबसे पहले पुरानी और नई प्रणालियों के बीच बराबरी का एक सुत्र तैयार करना था। यह योजना के पैरा 5 में निर्धारित तरीके से सभी छात्रों, कनिष्ठ डॉक्टरों, गृह अधिकारियों और अन्य लोंगों को फिर से डिजाई करके किया गया था। दूसरा प्रावधान स्नातकोतर पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश के संबंध में आवश्यक था। यह पैरा 5 के दूसरे उप-पैरा द्वारा किया गया था।

प्रत्यर्थी- डॉक्टर जिन्होने अप्रेल 1988 तक अपनी इंटर्नशिप और हाउस-जॉब पूरी कर ली थी और जिन्होने मार्च 1989 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश भी प्राप्त कर लिया था, उन्होनें रेजीडेंसी योजना के खण्ड 5 का लाभ उठाते हुए एम.एल.एन. कॉलेज में डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश की मांग की। उनके आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि, इस योजना का खण्ड 5 एक अस्थाई प्रावधान था। इसका उद्देश्य केवल उन व्यक्तियों को लाभान्वित करना था जो 22.08.1989 पर घर से काम पर थे, वे अकेले ही घर से काम पूरा करते हुए योजना का लाभ उठा सकते थे और वे व्यक्ति नहीं जिन्होने उस तारीख से बहुत पहले अपना घर का काम पूरा कर लिया था। इसके बाद इन डॉक्टरों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की ए खण्ड पीठ ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और कहा कि खण्ड 5 में प्रवेश का विशेषाधिकार बढाया गया है, के द्वारा डिग्री कोर्ट के द्वितीयवर्ष के प्रवेश के

विशेषाधिकार को बढ़ाया गया है। उन व्यक्तियों के लिए जो हाउस अंटेडेन्ट के रूप में 1 अगस्त 1987 के या उसके बाद कार्य कर रहे थे।

डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के रुप में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिये गृह अधिकारी 1 अगस्त, 1987 को या उसके बाद। राज्य के साथ-साथ कुछ डॉक्टर जो की हाउस जॉब में थे। 22.08.1989 और जिन्हे स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में भर्ती कराया गया था, योजना की राज्य की व्याख्या के आधार पर जिन्होंने अपनी सीटों को खो दिया या उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरुप उनके द्वारा यह अपील की गई। इन सीटों को प्राथमिकता दी गई है अपील करें।

जहां तक वर्तमान अपीलों का संबंध है, पक्षकारों ने यह आधार लिया है कि निवास योजना वैध है और जो यह परीकल्पित करती है कि एक व्यक्ति जिसने एक वर्ष के लिए हाउस जॉब पूरी कर ली है पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं (चाहे डिग्री हो) या डिप्लोमा)। एकमात्र विवाद यह है कि क्या यह प्रवेश केवल उन व्यक्तियों के लिय खुला था जो 22.08.1989 को एक हाउस जॉब में थे और उनके लिए जिन्होंने इसे 30 से पहले पूरा कर लिया है।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

(1) ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित करता हो (भले ही वह पहले से ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्र हो) कनिष्ठ

निवास के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेना चाहता है, प्रवेश के लिए पात्रता खण्ड जिन्हे वह पूरा करता है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्णय सही था कि उन्हें प्रवेश के विचार से बाहर नहीं रखा जा सकता है। डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश केवल इसलिए कि वे पहले से ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम में छात्र थे। {901 एच; 902 ए-बी}

(2) उन व्यक्तियों से पूछना, जिन्होने पहले ही एक साल का हाउस जॉब पूरा कर लिया था नौकरी, तीन साल की डिग्री के लिए दो साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम से गुजरना उनके लिए एक गंभीर बाधा होगी, क्योंकि पहले, वे दो साल/एक साल के बाद अपना स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते थे। उन्हे नई योजना में समायोजित करने के लिए राज्य ने नई योजना के तहत आवास नौकरियों के धारको को ''जूनियर रेजिडेन्ट (प्रथम वर्ष)'' के रुप में नामित किया। इसने आवास-नौकरी के धारकों को निवास योजना के तहत द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य बनाया।

(3) हालांकि, इस योजना को बढाया और परिवर्तित नहीं किया जा सका एक असीम प्रावधान में उन सभी व्यक्तियों के लिए जो किसी दूर के अतीत में अपनी हाउस जॉब पूरी कर चुके थे, डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करना संभव बनाता है। यही कारण है कि पैरा 5 लिमिटेड पुनर्विन्यास और प्रवेश के दायरे को भी सीमित करता है इसके

पहले भाग के समीकरण को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित कर दिया जो 1.08.1987 से हाउस जॉब पर काम कर रहे थे।

(4) उनके प्रवेश के उद्देश्य के लिए जो तिथि महत्वपूर्ण थी वह 30.09.1989 थी जो आवेदन भेजने की अंतिम तिथि। ऐसा होने पर, दूसरे उप-पैरा में ''उस-समय'' शब्दों का उपयोग किया गया है। पैरा 5 क्रियाशील शब्द है। वे स्पष्ट रुप से एक संन्दर्भ को मूर्त रुप देते है। समय का पूर्ववर्ती बिन्दु और यह केवल अवधि का संदर्भ हो सकता है, क्यूंकि 01.08.1987 जिसका पहले उप-पैरा में विशिष्ठ उल्लेख मिलता है और जो यह योजना के लागू होने के बाद की अवधि है। (905 डी-ई)

(5) 1.08.1987 के बाद हाउस जॉब करने वाले सभी व्यक्तियों को कवर पैरा 5 का दूसरा उप-पैरा कवर करता है।। शब्द ''कार्यकाल पूरा होने के बाद'' का यहां उपयोग किया जाना था क्यूंकि व्यक्तियों के वर्ग को भी संदर्भित किया गया है। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो 22.08.1989 को हाउस जॉब में थे। (905 एफ)

(6) यह स्पष्ट है कि शब्द ''हाउस ऑफिसर'', ''जूनियर रेजीडेन्ट' योजना के पैरा 5 में क्रमांक 1, 2 व 3 1.08.1987 से काम कर रहे थे, ऐसे सभी अधिकारियों को जो जूनियर रेजिडेन्ट के रूप में प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में कार्य कर रहे थे, को नामित किया गया। जूनियर रेजिडेन्ट-क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के रुप में। यह है कि इसलिए, रिट

याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अपीलकर्ता दोनो ही कनिष्ठ रेजिडेन्ट है। (प्रथम वर्ष) "और दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र होने चाहिए। (903 डी-ई)

(7) इस विषय पर उच्च न्यायालय के फैसलों से यह स्पष्ट है कि योजना की धाराओं की व्याख्या करना कोई आसान काम नहीं है। इस स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक समाधान ढूंढना राज्य पर निर्भर है कि छात्र समुदाय योजना में अस्पष्टता से पूर्वाग्रहस्त न हो। (909 एच; 910 ए)

मृदुला अवस्थी और अन्य बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य (1988) 3 एस.सी.आर. 762, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 4329-38/1990

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सी एम डब्लू पी 1989 के 18102, 18036, 22161, 22836 और 22877 में दिनांकित 30.05.1990 निर्णय और आदेश से।

कपिल सिब्बल, अतिरिक्त सालिसिटर जनरल, सतीश चन्द्र, सुश्री शोभा दीक्षित, प्रदीप मिश्रा, आर.के. वीरमानी, गोपाल सुब्रमण्यम हरीश एन.साल्वे और डी.के. गर्ग उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय (1990) 3 एस.सी.आर. द्वारा दिया गया था।

रंगनाथन, जे.

हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अपील के तहत उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए। लेकिन, चूंकि उठाया गया प्रश्न महत्वपूर्ण और कठिनाई का है, इसलिए हमने सलाह को विस्तार से सुना है। हम सभी याचिकाओं में अनुमति देते हैं और अपने निष्कर्ष के कारणों को विस्तार से बताने के लिए आगे बढते है। अपीलों के दोनों सेट यू.पी. राज्य में कनिष्ठ डॉक्टरों के लिए शुरु की गई। ''रेजीडेंसी स्कीम'' की शाखाएं है और उन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा आसानी से निपटाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम दो प्रकार के थेः

डिग्री और डिप्लोमा। डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष थी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा) में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता यह थी कि उम्मीद्वार को एमबीबीएस डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए थी, फिर एक साल की इंटर्नशि हो और फिर एक साल के लिए हाउस जॉब ''निवास योजना'' को 22.08.89 पर अधिसूचित किया गया था। यह राज्य में जूनियर डॉक्टरों द्वारा लम्बे समय तक चले आन्दोलन की परिणति थी। बेहतर विकास और सेवा स्थिति के लिए। इस योजना को 1.08.1987 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था, क्योंकि योजना के पैरा 8 में कहा गया है: उपरोक्त निवास योजना को 1 अगस्त 1987 से लागू माना जाएगा।

इस योजना के तहत, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए चुने गए प्रत्येक उम्मीदवार का कार्यकाल तीन साल का होगा जो पाठ्यक्रम का कार्यकाल भी होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों को उनके कार्यकाल के दौरान क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष जूनियर रेजिडेन्ट कहा जाना था। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए चुने गए प्रत्येक उम्मीदवार का कार्यकाल दो साल का होगा जो पाठ्यक्रम का कार्यकाल भी होगा और ऐसे सभी उम्मीदवार को क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष जूनियर रेजिडेन्ट कहा जाना था। दूसरे शब्दों में, डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि बढाकर तीन वर्ष और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि बढाकर दो वर्ष कर दी गई थी। हालांकि, समान रुप से, एक में एक वर्ष के अनुभव की पात्रता की आवश्यकता हाउस-जॉब को छोड दिया गया। शुद्ध परिणाम यह था कि स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए एक एमबीबीएस् डिग्री लेने के बाद आवश्यक कुल अवधि पहले की तरह ही रही।

नई योजना द्वारा शुरु किए गए संशोधनों के लिए दो उद्देश्यों के लिए कुछ अस्थाई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता थी। पहला यह था कि पुरानी और नई प्रणालियों के बीच समीकरण का एक सुत्र तैयार करें। यह स्कीम के पैरा 5 में निर्धारित तरीके से सभी छात्रों, कनिष्ठ डॉक्टरों, गृह अधिकारियों और अन्य लोंगों को फिर से डिजाइन किया गया था। योजना। मूल अधिसूचना हिंदी में है लेकिन इसका मुफ्त अनुवाद है।

उपरोक्त पैरा का पहला भाग, जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले में दिया गया है, इस प्रकार हैः

> ‘‘उपरोक्त योजना के लागू होने पर, सभी गृह अधिकारी, जूनियर रेजिडेन्ट प्रथम वर्ष काम कर रहें हैं। 1 अगस्त, 1987 से और इसी तरह काम करने वाले सभी जूनियर डॉक्टर (‘‘सभी जूनियर डॉक्टर समान रुप से काम कर रहे हैं’ शायद एक बेहतर अनुवाद है) निम्नलिखित में परिवर्तित हो जाएंगें: एस. नहीं। राष्ट्रपति पदनाम इस पर पदनाम का प्रवर्तन निवास योजना।

1 गृह अधिकारी/प्रदर्शनकारी, प्रथम वर्ष, (प्रेसिडेंट पद)- जूनियर रेजिडेन्ट प्रथम वर्ष (पदनाम का प्रवर्तन)

2. जूनियर रेजिडेन्ट/आर.एम.ओ. प्रथम वर्ष/आर.एस.ओ. प्रथम वर्ष/प्रदर्शनकारी दूसरा वर्ष/डिग्री छात्र प्रथम वर्ष/पी.जी. डिप्लोमा छात्र प्रथम वर्ष (प्रेसिडेंट पद)- जूनियर रेजिडेन्ट, दूसरा वर्ष (पदनाम का प्रवर्तन)

3॰ सीनियर रेजिडेन्ट/आर.एम.ओ. द्वितीय वर्ष/आर.एस.ओ. दूसरा वर्ष प्रदर्शक द्वितीय वर्ष/आर.जी.ओ. द्वितीय वर्ष/प्रदर्शनकारी, तीसरा वर्ष/पी.जी. डिग्री छात्र द्वितीय वर्ष/रैजिस्ट्रार (प्रेसिडेंट पद)- जूनियर रेजिडेन्ट, तीसरा वर्ष (पदनाम का प्रवर्तन)

दूसरा प्रावधान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश के संबंध में आवश्यक था। यह दूसरे उप-पैरा या पैरा 5 द्वारा किया गया था जो इस प्रकार थाः-''उसी समय (''इसके साथ ही साथ'') प्रवेश और उस समय काम कर रहे गृह अधिकारियों का पंजीकरण (''यू.एस. समय'') से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा)तक पाठ्यक्रम) उनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद किया जाएगा और योग्यता के आधार पर एमबीबीएस् और घर-नौकर'' '। (कोष्ठक में शब्द मूल हिन्दी अभिव्यक्ति देते है।

उपयोग किया गया; (1990)3 एस.सी.आर. 900 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट योजना के प्रावधान स्पष्ट रुप से यह नहीं कहतें है कि उपरोक्त दूसरे उप-पैरा के तहत काम करने वाले व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर निवास योजना के डिग्री पाठ्यक्रम (जूनियर रेजिडेन्ट-द्वितीय वर्ष) के दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। डॉ. संदीपा श्रीवास्तव के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा कुछ अलग सोच को अपनाया गया प्रतीत होता है (जिसका हम बाद में उल्लेख करेंगें)। लेकिन, जहां तक वर्तमान अपीलों का संबंध है, सभी पक्ष इस आधार पर आगे बढें है कि यह योजना वैध है और यह परिकल्पना की गई है कि एक व्यक्ति जिसने एक वर्ष के लिये हाउस जॉब पूरी कर ली है, वह पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष (चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा) में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। एकमात्र विवाद यह है कि क्या यह प्रवेश केवल उन व्यक्तियों के लिए खुला है जो 22.08.89 पर एक हाउस जॉब में थे और इसे 30.10.1989 (इसके बाद 'अपीललांट' के रुप में संदर्भित) से पहले

पूरा किया था या उन सभी व्यक्तियो के लिए जो 01.08.87 पर या उसके बाद हाउस जॉब में थे। यह सवाल तब उठा जब कई डॉक्टर (जिन्हे इसके बाद 'रिट याचिकाकर्ता के रुप में संदर्भित किया गया है) जिन्होने अप्रेल, 1988 तक अपनी एमबीबीएस इंटर्नशिप और हाउस-जॉब पूरी कर ली थी और जिन्होने (एक के लिए छोडकर) मार्च 1989 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश भी प्राप्त कर लिया था, उन्होने निवास योजना के खण्ड 5 का लाभ उठाते हुए इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज ('एम.एल.एन. कॉलेज, संक्षेप में) में डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में उसी या किसी अन्य विशेषता में प्रवेश लेने की मांग की। उनके आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि योजना का प्रासंगिक खण्ड एक अस्थाई प्रावधान था जिसका उद्देश्य केवल उन व्यक्तियों को लाभान्वित करना था जो 22.08.1989 को हाउस जॉब कर रहे थे। वे अकेले ही इस योजना का लाभ उठा सकते थे, जब तक जैसे ही वे घर का काम पूरा नहीं कर लेते थे, न कि उन लोगों के लिए जिन्होनें अपना हाउस जॉब इस तारीख से बहुत पहले ही पूरा कर लिया है। रिट याचिकाकर्ता अदालत गए और इस बार वे सफल रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने नियम 5 की व्याख्या करते हुए कहा कि नियम 5 ने उन सभी व्यक्तियों को, जो 1 अगस्त, 1987 को या उसके बाद गृह अधिकारी के रुप में काम कर रहे थे, डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के लिए प्रवेश के विशेषाधिकार का विस्तार किया। राज्य के साथ-साथ कुछ डॉक्टर जो 22.08.89 को हाउस जॉब में

थे और जिन्हे योजना कीराज्य की व्याख्या के आधार पर स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरुप अपनी सीटें खो दी थी, उन्होने इन अपीलों को प्राथमिकता दी।

उच्च न्यायालय के विचार के लिए चार प्रश्न उठेः-

(1) क्या योजना के नियम 5 की रियायत केवल हाउस जॉब में डॉक्टरों के लिए सीमित थी, जो दिनांक 22.08.89 को हो या उन सभी के लिए जो 1.08.87 को हाउस में थे या बाद में भी।

(2) एक उम्मीद्वार है जिसे पहले ही भर्ती किया जा चुका है और जिसका डिप्लोमा कोर्स चल रहा है वह नियम-5 के अंतर्गत डिग्री कोर्स में प्रवेश के योग्य है?

(3) क्या यह एक ऐसे उम्मीद्वार के लिए खुला है जो एक विशिष्टता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में छात्र है और जो किसी अन्य विशिष्ट योग्यता वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है।

(4) क्या डिप्लोमा पाठ्यक्रम से गुजरने वाले उम्मीद्वार के लिए इसे बीच में छोडने और डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति है?

उच्च न्यायालय ने बाद के दो प्रश्नों पर कोई राय व्यक्त नहीं की और इसे कॉलेज के प्राचार्य पर छोड दिया कि वे उचित समय पर इसका निर्णय लें, लेकिन रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पहले दो प्रश्नों का उत्तर दिया।

हम यहां केवल इन दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम इनमें से दूसरे प्रश्न को पहले ले सकते हैं। रिट पिटिशनर्स का कहना है कि इस प्रश्न का सीधा उत्तर एक अधिसूचना जो कि दिनांक 13.08.1987 को जारी की गई थी द्वारा प्रदान किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (1973 का अधिनियम 10) की धारा 28 (5) के साठ पठित (संविधान के अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के सपठित धारा 28 (5)) अनुसरण में राज्य के राज्यपाल द्वारा 1974 के संशोधित अधिनियम 29 पर जारी किया गया। यह उत्तरप्रदेश अधिसूचना पहले की अधिसूचना दिनांक 15.12.1982 (जैसा की बाद में संशोधित किया गया) में संशोधन को प्रभावित करती है।

> ‘‘(7ए) यदि किसी उम्मीद्वार को किसी एक विशेषता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, तो वह किसी अन्य विशेषता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा। संदेहो को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी उम्मीद्वार को किसी एक विशेषता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है तो उसे उसी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के और अधिक विशेषता वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। यदि यह सही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी भी रिट

याचिकाकर्ता को पंजीकरण और प्रवेश के लिए विचार से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें पहले किसी विशेषज्ञता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है। अपीलार्थीयों की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि नई योजना की घोषणा पर इस नियम ने अपना बल खो दिया है। यह समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इस सिद्धान्त को जरूरी तबदीलियों के साथ निवास योजना पर भी लागू किया जा सकता था। लेकिन अगर यह सही है और इस पैरा को पूरी तरह से विचार से बाहर रखा गया है, तो ऐसा कोई नियम नहीं जो किसी व्यक्ति (भले ही वह पहले से ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्र हो) कनिष्ठ निवास के दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पात्रता खण्ड जिन्हे वह पूरा करता है, की मांग करने से रोकता है। उच्च न्यायालय, इसलिए सही था, इस सवाल पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते हुए कि क्या कोई रिट है। याचिकाकर्ता किसी विशेष विशेषता में भर्ती होने के पात्र है, यह मानते हुए कि उन्हे विचार से बाहर नहीं रखा जा सकता है कि डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश केवल इसलिए कि वे पहले से ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम में छात्र है।"

पहला प्रश्न हालांकि दूसरे से मुश्किल था। हमने दोनो तरफ के तर्कों पर विचार किया सावधानीपूर्वक विचार किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को भंग करने का कोई कारण नहीं है। योजना के लागू होने से पहले सभी उम्मदीवार जिन्होंने अपनी एमबीबीएस के साथ्ज्ञ एक साल की इन्टरशीप और एक साल का हाउस जॉब पूरा किया था वे स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र थे और विशिष्ट अभ्यर्थी विशिष्ट स्नातकोत्तर योग्यता में प्रवेश के लिए कई बार प्रयास कर सकता है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए वह किस बेच से संबंधित है और किसी विशिष्ट साल में उसने एमबीबीएस में प्रवेश किया किस विशिष्ट साल में उसने एमबीबीएस की फाईनल परीक्षा पास की। यह स्वतंत्रता नई योजना आने पर सभी एमबीबीएस स्नातकों को जिन्होंने अपनी एक वर्ष को इन्टरशीप पूरी कर ली है। इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए कि किस वर्ष में उन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री की परीक्षा पास की यह सभी अभ्यर्थियों के लिए खुली थे जो कि तीन साल के डिग्री कोर्स या दो साल के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हो। यह विवादित नहीं है कि प्रश्न केवल यह था उनमें से कोई द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए योग्य है इस आधार पर उन्होंने अपनी हाउस जॉब पहले ही पूर्ण कर ली। इस प्रश्न का जवाब उस निर्वचन पर आधारित है जो कि स्पष्ट नहीं है। खण्ड-5 रेजीडेन्सी स्कीम का योजना की व्याख्या करते समय, सबसे पहले यह इंगित करना आवश्यक है कि अधिसूचना की प्रस्तावना में दो गुना

उद्देश्य निर्धारित किया गया है- एक नीति/प्रक्रिया लिखना (ए) विभागों में मौजूदा देशी निकायों को समकक्ष पदनामों में बदलने के लिए और (बी) विभिन्न डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या के विनिर्देश के लिए और'' '' (जाहिरा तौर पर, यह पढना चाहिएः '' योग्यता, परीक्षा या चयन''। ध्यान में रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना को 1.8.87 से प्रभावी किया गया था। जिन व्यक्तियों ने पहले ही एक साल की हाउस जॉब पूरी कर ली थी, उन्हे तीन साल की डिग्री/दो साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए कहना उनके लिए एक गंभीर बाधा होगी, क्यूंकि पहले, वे दो साल/एक साल के बाद अपनी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त कर सकते थे। उन्हे नई योजना में समायोजित करने के लिए-

राज्य में नई योजना के तहत आवास नौकरियों के धारकों को ''जूनियर रेजीडेन्टस (प्रथम वर्ष)'' के रुप में नामित किया है। इसने आवास-नौकरी के धारकों को निवास योजना के तहत द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के योग्य बनाया। अपीलार्थीयों के प्रत्युत्तर में यह कहा गया है कि बडी संख्या में अभ्यर्थी तारीखें जिन्होने दस साल पहले ही अपना एमबीबीएस पूरा कर लिया था और कुछ उम्मीद्वार जो स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के कगार पर थे, उन्होने अपीलार्थयों और रिट याचिकाकर्ताओं के साथ जूनियर रेजीडेन्टस (द्वितीय वर्ष) के रुप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। इस प्रकार की परिस्थिति

अव्यावहारिक होगी। जाहिर है, इस योजना को बढाया नहीं जा सका और एक असीम प्रावधान में परिवर्तित नहीं किया जा सका, जिससे उन सभी व्यक्तियों के लिए डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करना संभव हो गया, जिन्होने पूर्व में में अपनी हाउस जॉब पूरी कर ली थी। यही कारण है कि पैरा 5 ने पुनर्विन्यास और समायोजन के दायरे को सीमित कर दिया। इसके पहले भाग ने उपरोक्त समीकरण को सीमित कर दिया जो केवल उन व्यक्तियों के लिए संदर्भित था जो 1.8.1987 से हाउस जॉब में थे। उच्च न्यायालय का यह कहना स्पष्ट रुप से सही था कि क्रम संख्या 1 के विरुद्ध पैरा 5 में तालिका के स्तंभ में उपयोग किए गए शब्द ''प्रथम वर्ष केवल ''दानव स्तरीकरण'' को नियन्त्रित करते है। यह स्पष्ट है कि हाउस जूनियर रेजीडेन्ट और सीनियर रेजीडेन्ट शब्द जो कि क्रम संख्या 1, 2, 3 में प्रयोग किये गये है, उन्हें दोबारा बनाया गया उन सभी अधिकारियों के लिए जो 01.08.1987 से जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में कार्य कर रहे है। रेजिडेन्सी स्कीम पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र होने चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा दो कारणों से नहीं हो सकता है। एक यह है कि पैरा 5 का दूसरा उप-पैरा केवल उन लोगों तक सीमित है जो हाउस ऑफिसर्स थे, 22.8.89 को है। हम सोचते हैं कि यह तर्क है उच्च न्यायालय द्वारा सही खारिज किया गया।

इस निर्माण को स्वीकार करने का अर्थ होगा पैरा 5 के दो भागों का पृथक्करण औरा पैरा 5 के पहले पैरा में उपयोग किए गए ''1 अगस्त

1987 सं' शब्दों के लिए' 22 अगस्त 1989 क' शब्दों का प्रतिस्थापन। '' उस समय'' शब्द स्पष्ट रुप से पैरा 5 के दो भागों के बीच एक संबंध स्थापित करते है और केवल अवधि को संदर्भित कर सकतें है। जिसका उल्लेख पहले भाग में किया गया है। 1 अगस्त 1987 सं'। यह देखना मुश्किल है कि पैरा 5 के दो भागों द्वारा दो अलग-अलग अवधियों के संदर्भ का इरादा कैसे किया जा सकता था। यह भी स्पष्ट है कि यह योजना, हालांकि 22.8.89 पर घोषित की गई, से प्रभावी होनी थी। 1.8.1987 यही कारण है कि उस तारीख को एक रेखा खींची जाती है और सभी व्यक्ति जो उस तारीख से गृह अधिकारी, जूनियर रेजिडेन्ट डॉक्टर या वरिष्ठ निवासी डॉक्टर के रुप में काम कर रहें हैं, उन सभी को नए नियम में शामिल किया जाता है।

इस तरह के एकीकरण को आंशिक रुप से पढने का कोई औचित्य नहीं है, जैसा कि राज्य द्वारा तक्र दिया गया है। यह तर्क दिया कि यह योजना राज्य में कनिष्ठ डॉक्टरों के साथ बातचीत का परिणाम थी जो सेवा की बेहतर शर्तो और उच्च परिलब्धियों के लिए आंदोलन करना और उनके साथ समझौता केवल इतना था कि उच्च परिलब्धियों का भुगतान डब्ल्यू.ई.एफ.1.8.87 से किया जाएगा। इस याचिका को साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री उच्च न्यायालय या हमारे समक्ष नहीं रखी गई थी। लेकिन यह मानते हुए भी कि बातचीत और समझौते का दायरा सीमित था, हमें इसकी भाषा में पैरा 5 के दायरे की व्याख्या उसकी भाषा में करनी

होगी। पैरा 5 में 1.08.1987 के बाद की अवधि का संदर्भ पैरा 8 में इस घोषणा के साथ मेल खाता है कि योजना को 1.08.87 पर लागू माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि 22.08.89 पर अधिसूचित योजना में कहा गया है कि यह योजना सभी कॉलेजों और अस्पतालों में स्नातक/स्नातकोत्तर 'प्रशिक्षण' में वांछित सुधार के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसरण में शुरु की गई है, लेकिन कनिष्ठ डॉक्टरों के वेतनमान में संशोधन का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए, इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि तारीख 1.8.87 का महत्व केवल वेतनमान के मामले में है और कुछ नहीं। इसलिए यह आपत्ति चलने योग्य नहीं है।

राज्य और अपीलार्थीयों द्वारा दूसरा मुद्दा यह है कि इस योजना के तहत रिट याचिकाकर्ता पहले से ही ''जूनियर रेजिडेन्ट-द्वितीय वर्ष' हैं क्योंकि वे पहले से ही स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में हैं और इसलिए वे डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं, जहां उन्हें जूनियर रेजिडेन्ट-द्वितीय वर्ष' के रुप में नामित किया जाएगा। हमारे विचार में, आपत्ति असमर्थनीय है। सबसे पहले, यह केवल इस तर्क का एक बदलाव है कि पहले से ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम से गुजर रहे व्यक्ति को डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है, जिसे हम पहले ही खारिज कर चुकें है। लेकिन इसके अलावा, रिट याचिकाकर्ताओं को द्वितीय वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम में भर्ती होने और

डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बजाय वहां ''जूनियर रेजिडेन्ट-द्वितीय वर्ष' कहे जाने में कुछ भी गलत नहीं है। इस संदर्भ में, यह इंगित करना आवश्यक है कि उन्हे केवल मार्च 1989 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है और वे डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्राप्त शिक्षा की अवधि के लिए कोई श्रेय नहीं मांग रहे है।

तब यह तर्क दिया जाता है कि ''हम समय'' शब्द में आ रहे हैं। योजना के पैरा 5 का दूसरा भाग वास्तव में ''इस समय'' या ''इस समय'' या ''वर्तमान मैं के लिए एक गलती है। इस आशय के समर्थन में, यह बताया गया है कि चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने सरकार के सचिव को 2.11.1989 पर पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि 22.8.89 की अधिसूचना में ''उस समय'' के स्थान पर वर्तमान शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए ताकि उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट हो' । यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के ''कार्यकाल पूरा होने के बाद'' प्रवेश के लिए पात्र होने का संदर्भ हाउस-जॉब से यह भी स्पष्ट होता है कि जिन व्यक्तियों ने पहले ही पूरा कर लिया था। 1987 या 1988 में उनकी घेरलू नौकरियां विचाराधीन नहीं है। हम सहमत नहीं हो सकते। जब अधिसूचना ''उस समय'' की बात करती है, तो हम इसे अलग तरह से नहीं पढ सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशक के दिनांकित 2.11.1989 के पत्र में केवल प्रत्युत्तर शपथ पत्र में एक संदर्भ मिलता है और रिट याचिकाकर्ताओं को इसे पूरा करने का कोई अवसर नहीं मिला है। राज्य ने इस पत्र या उस पर की गई कार्यवाही का

कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। इन कठिनाईयों के अलावा, पत्र स्पष्ट रुप से अधिसूचना की सामग्री में बदलाव लाने का प्रयास करता है और स्पष्टीकरण के लिए एक सरल अनुरोध नहीं है जैसा कि इसका तात्पर्य है। सबसे अच्छा, यह केवल अधिसूचना के बारे में निदेशक की समझ को दर्शाता है और रिट याचिकाकर्ताओं या न्यायालय को बाध्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं या राज्य द्वारा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या निदेशक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और सुझाए गए संशोधन के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित संशोधन केवल ऐसे प्रकाशन पर ही प्रभावी हो सकता है। इस तक्र का एक प्रस्ताव इंगित किया जा सकता है कि 22.8.89 की अधिसूचना स्वयं राजपत्र में केवल इस पर प्रकाशित की गई थी 25.11.89, निदेशक के पत्र के काफी बाद। यह मानते हुए भी कि उनके सुझााव को तब से स्वीकार कर लिया गया है और ''उस समय'' शब्दों को बाद में एक उचित अधिसूचना द्वारा ''वर्तमान समय'' शब्दों से बदल दिया गया है, वह संशोधन हमारे सामने पक्षकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है। उनके प्रवेश के उद्देश्यों के लिए मैटरियल की तारीख 30.9.89 थी, वह अंतिम तारीख जिसके द्वारा आवेदन भेजे जाने थे। इस प्रकार, पैरा 5 के दूसरे उप-पैरा में उपयोग किए गए शब्द ''उस समय'' क्रियाशील शब्द है। वे स्पष्ट रुप से एक पूर्ववर्ती बिंदु के सदर्भ को मूर्त रुप देतें है। समय और यह केवल 1.8.87 के बाद की अवधि का संदर्भ हो सकता है, जिसका पहले उप-पैरा में विशिष्ट उल्लेख मिलता है और जो

योजना के लागू होने के बाद की अवधि है। इस प्रकार, 1.8.87 के बाद हाउस जॉब करने वाले सभी व्यक्तियों को पैरा 5 के दूसरे पैरा द्वारा कवर किया जाता है।''

''

जाना था क्योंकि संदर्भित व्यक्तियों के वर्ग में वे लोग भी शमिल थे जो 22.8.89 पर घरेलू नौकरियों में थे। वास्तव में इस योजना को एम.एल.एन. कॉलेज के प्राचार्य और शायद अन्य प्राचार्यो ने भी इसी तरह समझा था। हम पाते हैं कि प्राचार्य. एम.एल.एन. कॉलेज द्वारा जारी विज्ञापन की शर्तें, जिन पर रिट याचिकाकर्ताओं ने जवाब दिया था, उन्होने यह कहाः ''उम्मीद्वारों को एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए. एक वर्ष का अनिवार्य आवर्तन इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और 30 अक्टूबर तक संबंधित विषय में एक वर्ष की हाउसमैनशिप पूरी करनी चाहिए/पूरी होनी चाहिए।

यह कॉलेज के प्राचार्य द्वारा योजना की समझ थी और, निश्चित रूप से, रिट याचिकाकर्ताओं ने इन आवश्यकताओं को पूरा किया। इसलिए, दूसरे विवाद में भी कोई सार नहीं है।

राज्य की ओर से सुश्री शोभा दीक्षित ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या दो प्रकार की बड़ी कठिनाइयाँ पैदा करती है। पहला यह है कि हालांकि उच्च न्यायालय का निर्णय केवल इलाहाबाद के एम. एल. एन. कॉलेज से संबंधित है, लेकिन पूरे राज्य में स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी इसी तरह के दावे किए गए हैं और कुछ मामलों में उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले के बाद इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कैंडीडेट्स जिन्होंने प्रवेश प्राप्त कर लिए हैं, वे अब अपनी सीटों के नुकसान का सामना कर रहे हैं और लगभग एक वर्ष के अध्ययन के लाभ का सामना कर रहे हैं जो वे पहले ही कर चुके हैं। हमारी राय में इस तर्क का कोई बल नहीं है। यह कहना सही नहीं लगता कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय पूरे राज्य में प्रवेश को प्रभावित करेगा।

उत्तरदाताओं ने अपने जवाबी हलफनामे के पैरा 13 में इस प्रकार कहा हैः-

यू. पी. के अन्य मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पुराने नियमों के आधार पर किया गया है अर्थात सरकार, अधिसूचना दिनांक 15.12.1982 और 13.8.1987 और जिन छात्रों ने अपना घर का काम बहुत पूरा कर लिया है उनके अनुसार डिग्री और 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम दिनांकित निवास योजना की शुरुआत के बाद दिनांकित 22.8.89.''

यह अनियंत्रित बना हुआ है। इसके अलावा, अन्य कॉलेजों में किए गए प्रवेश की वैधता उन लोगों पर निर्भर करेगी जिन्होंने वहां प्रवेश के लिए आवेदन किया था। यदि एम. एल. एन. महाविद्यालय की तरह पहले के गृह अधिकारियों के समूहों ने भी उन महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए

आवेदन किया था और उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, तो यह पद वर्तमान के समान हो सकता है। हालाँकि, यदि ऐसे व्यक्तियों ने बिल्कुल भी आवेदन नहीं किया था या उन पर विधिवत विचार नहीं किया गया था, तो उनके विचार के लिए अब कोई सवाल नहीं उठ सकता है। नहीं।

इसलिए, पूर्ण किए गए प्रवेशों के अनुचित संशोधन के परिणामस्वरूप होने की संभावना है। यह याचिका कि अपीलकर्ता पाठयक्रम में लगभग एक वर्ष पूरा कर चुके हैं और उन्हें इसका लाभ नहीं खोना चाहिए, को भी अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि रिट याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों से उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें केवल विशिष्ट समझ पर पाठ्यक्रम में बने रहने की अनुमति दी जा रही है कि उनके प्रवेश रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगे।

राज्य के वकील द्वारा दिया गया दूसरा बिंदु यह है कि यह मजबूर करता है हाउस जॉब करने वाले छात्रों के समूह-प्रतियोगिता का सामना करने के लिए नौकरी इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा दी गई, कुछ टिप्पणियों का उल्लेख किया अपने बैन से पहले और उसके अनुसार सहविवाध के विरूद्ध है। अभ्यार्थियों को मेरिट की जो विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न राज्यों को प्राप्त की है, की तुलना की जाए।

विभिन्न परीक्षाओं और विभिन्न राज्यों में उम्मीदवारों की संख्या की जाए। इस विवाद में हम बल नहीं देखते, जैसा कि पहले बताया गया है कि

इस योजना के आने के बाद पहले और बाद में चिकित्सा स्नातकों के बीच खुली प्रतिस्पर्धा थी और होगी जिन्होंने हाउस जॉब या इंटर्नशिप पूर्ण कर ली है, वह किसी भी बैच से संबंधित हैं। यह अपीलार्थियों की ओर से दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि, हालांकि रिट याचिकाकर्ता, पद पर प्रवेश प्राप्त करते समय स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पहले के बैचों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, उन्हें कुछ वरीयता दी गई थी। हम नहीं जानते कि किस आधार पर ऐसी वरीयता दी गई थी और अब इस पहलू पर जांच करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तथ्य यह है कि उनके साथ विचार किया गया था। उनके लिए पहले दो छात्रों के समूहों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना आवश्यक हो गया है छात्रों के समूह के लिए।

इसके विपरीत, जैसा कि उच्च न्यायालय ने इंगित किया है, यह है राज्य द्वारा अनुरोध की गई निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकती है। हम पहले यह मान चुके हैं कि हालांकि यह योजना शुरू की गई है 1989 में लेकिन 1.8.87 से प्रभावी है। यदि ऐसा है, तो हाउस जॉब जो कि 1989 से कार्य कर रहे है, को अकेले बेहतर स्थिति में रखना होगा, अपेक्षा उनके जिन्होंने अपनी हाउस जॉब 1987, 1988 या 1989 से पहले पूर्ण कर ली है का रिजल्ट उनके पक्ष में असमानता औश्र याचिका कर्ताओं के विरूद्ध निश्चित है। वास्तव में योजना का मुख्य उद्देश्य और योजना को 01.08.1987 में प्रभाव देना है।

राज्य की ओर से एक और विवाद उठाया गया और अपीलार्थी एक मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। डॉ. संदीपा श्रीवास्तव (सिविल विविध रिट याचिका सं-13419/89) एक याचिका जो कि विशेष अनुमति की जो इस न्यायालय द्वारा खारिज की गई, (एसएलपी 1380/89 को 6.4.90)। डॉ. श्रीवास्तव ने 1987 में अपनी एमबीबीएस् पूर्ण की और जून 1988 में एक साल की इंटर्नशिप की और हाउस जॉब में प्रवेश के लिए आवेदन किया लेकिन प्रवेश तय होता उससे पहले निवास योजना शुरू की गई थी। उसने चुनौती दी है, द्वारा प्रदत्त डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश को चुनौती जो एम. एल. एन. कॉलेज, उनकी वरीयता में, एक डॉ. सुरभी राय के लिए जो कि अपनी एमबीबीएस 1987 में पूर्ण कर चुकी थी और अपनी इन्टरशीप 1988 मे और हाउस जॉब मे थी 22.08.1989 को। उस मामले में एक बहुत ही अजीब स्थिति उत्पन्न हुई है। डॉ. सुरभी राय ने पहले वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया था न कि नए निवास पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में, हालांकि वह 22.8.89 पर हाउस जॉब पर थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह यहां रिट याचिकाकर्ताओं की तरह दूसरे वर्ष के लिए आवेदन नहीं कर सकी क्योंकि उसकी हाउस जॉब 30.10.89 तक पूरी नहीं की जा सकी, जिस तारीख का उल्लेख पत्र में किया गया है।

विज्ञापन में थी जिससे हम संबंधित हैं। डॉ. श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय (ए) के समक्ष तर्क दिया कि केवल 1983 बैच के छात्र जिन्होंने 1988 में एमबीबीएस् उत्तीर्ण किया था, वे डिग्री में प्रवेश के लिए पात्र थे,

ना कि वे लोग जो पहले उत्तीर्ण हुए थे, और (बी) कि डॉ. सुरभी राय को जूनियर रेजीडेंसी पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में नहीं, बल्कि दूसरे वर्ष में प्रवेश लेना चाहिए था। अदालत ने पहले तर्क को खारिज कर दिया जो स्पष्ट रूप से असमर्थनीय था और यह रिट याचिका के निपटारे के लिए पर्याप्त था। हालाँकि, अदालत ने दूसरे विवाद पर भी विचार किया और इसे इस प्रकार निपटायाः

> ‘‘ याचिकाकर्ता के दूसरे तर्क का भी कोई बल नहीं है। इस प्रस्ताव के लिए, याचिकाकर्ता ने सरकारी आदेश दिनांक 22.8.89 के पैरा 5 के अंतिम भाग पर आधारित किया है। सरकारी आदेश के पैरा 5 में कहा गया है कि 1 अगस्त, 1987 से काम कर रहे हाउस ऑफिसर्स और जूनियर डॉक्टरों को प्रथम वर्ष के जूनियर रेजिडेंट में परिवर्तित किया जाएगा। इस पैरा में दिए गए चार्ट के अनुसार द्वितीय वर्ष आदि। इस पैरा का अंतिम भाग इन गृह अधिकारियों के बारे में बताता है, जो 1.8.87 से काम कर रहे थे। यह पैरा मानदंड प्रदान नहीं करता है या उन तिथियों के प्रवेश में संबंधित नहीं है, जो प्रथम वर्ष की हाउस नौकरी में शामिल हुए हैं और जिन्होंने अभी तक प्रथम वर्ष भी पूरा नहीं किया है। उन लोगों के मामले, जो हाउस जॉब के पाठ्क्रम में शामिल हुए हैं, लेकिन निवास की नई योजना शुरू होने तक

पूरा नहीं कर सके हैं, उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और 16.9.1989 पर मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशक की बैठक में विचार किया गया है। इस संकल्प का पैरा 6। यह निर्धारित किया गया है कि निवास योजना के प्रवर्तन के बाद गृह नौकरी के पाठयक्रम को समाप्त कर दिया गया है और जो उम्मीदवार हाउस जॉब का प्रशिक्षण ले रहे हैं, वे अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और इस तरह, उन सभी उम्मीदवारों को, जो हाउस जॉब का प्रशिक्षण ले रहे हैं, योग्यता के आधार पर जूनियर रेजीडेंसी के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों का यह संकल्प निष्पक्ष प्रतीत होता है। चूंकि हाउस जॉब के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है और इस पाठ्यक्रम से गुजरने वाले उम्मीदवार संभवतः अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और यदि उन्हें जूनियर रेजीडेंसी के पहले वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो उन्हें बड़ी कठिनाई और अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे अपने हाउस जॉब के पाठ्यक्रम को जारी रखने के अपने अधिकार से सत्र के बीच में वंचित हो जाएंगे।"

जब हाउस जॉब का कोर्स समाप्त कर दिया गया है, तो इस कोर्स से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए यह असंभव है कि वे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। वास्तव में संख्या 3 को खुशी होती, अगर उसे हाउस जॉब के एक साल के पाठ्यक्रम को जारी रखने और समाप्त करने की अनुमति दी जाती, क्योंकि उस स्थिति में कुछ महीनों के बाद उसे जूनियर रेजीडेंसी के दूसरे वर्ष में प्रवेश मिल जाता और वह याचिकाकर्ता और अन्य सभी से वरिष्ठ हो जाती, जो जूनियर रेजीडेंसी के पहले वर्ष में शामिल होने वाले हैं।

बेशक अब, लेकिन हाउस जॉब की प्रणाली के उन्मूलन के कारण प्रत्यर्थी नं 3 पाठयक्रम जारी रखने के लिए और इस तरह, उसे जूनियर रेजीडेन्सी कोर्स के पहले वर्ष में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। हम फैसले के इस हिस्से के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या उससे कोई अपील की गई है। यह है। यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि हमारे सामने सभी अपीलकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जो 22.8.89 पर हाउस जॉब में थे और डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश का दावा कर रहे हैं। इसलिए, हम केवल संतुष्ट होंगे। स्वयं यह कहकर कि, चूंकि हमसे पहले सभी पक्ष इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि अपीलकर्ताओं के पद पर व्यक्ति जूनियर रेजिडेन्ट- द्वितीय वर्ष के रूप में प्रवेश के लिए पात्र है, इसलिए हमें इस बिंदु पर डॉ. संदीपा श्रीवास्तव के मामले में निर्णय की शुद्धता पर विचार करने के लिए नहीं कहा जाता है। यह एक ऐसा मामला था जो डिग्री पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश से

संबंधित था और क्योंकि योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलार्थियों या डॉ. सुरभि राय को जूनियर रेजिडेन्ट के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले वर्ष में उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से सही था। इसलिए उस मामले में एसएलपी की बर्खास्तगी हमारी वर्तमान चर्चा को प्रभावित नहीं करती है।

हमारे समक्ष अपील में उच्च न्यायालय का निर्णय, डॉ. संदीपा श्रीवास्तव के मामले में दिया गया निर्णय और अन्य निर्णय सुश्री शोभा दीक्षित ने जिसका एक संदर्भ दिया, हालांकि, यह स्पष्ट करता है कि योजना के खंडों की व्याख्या, किसी भी तरह से, एक आसान कार्य व्यवहार में भी, जिस आधार पर प्राचार्य-कम से कम एम. एल. एन. कॉलेज के प्राचार्य-आगे बढ़े, वह चिकित्सा शिक्षा निदेशक के दिनांकित 2.11.89 के पत्र के साथ संगत नहीं दिखता है। इस स्थिति में, हम सोचते हैं कि यह राज्य पर निर्भर है कि वह यह सुनिश्चित करे। एक व्यावहारिक समाधान का पता लगाए जिससे छात्र समुदाय योजना में अस्पष्टताओं से पूर्वाग्रहित नहीं हो। इस संदर्भ में, मृदुला अवस्थी और अन्य बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य, (1988) 3 एससीआर 762ः के मामले में इस न्यायालय के निर्देशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था।

> ‘‘ इस पृष्ठभूमि में हमारा मानना है कि द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी दावों के कारण बनाया गया पास फ्रेशर्स और

सीनियर्स को तैयार रहना पड़ता है। समाधान-फिर भी मनमाना और स्वीकार्य और संतोषजनक नहीं जितना हो सके। हम पाते हैं कि दो साल का डिग्री कोर्स विशेषज्ञता-वार 149 सीटें हैं जबकि तीन साल की डिग्री पाठ्यक्रम में 139 सीटें हैं। सुविधा के लिए बुलेटिन के पृष्ठ 4 पर विवरण उपलब्ध कराए गए है। जानकारी दी। यह बताया जा सकता है कि कुल 270 रिक्तियों के मुकाबले उम्मीदवार 1003 (डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक साथ) वरिष्टों के लिए, और वहाँ हैं। 331 दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 205 रिक्तियों के मुकाबले उम्मीदवार फ्रेशर्स के लिए। कुछ और सीटें प्रदान करने की दृष्टि से वरिष्ठों के लिए हमने श्री राव को यूनिवर्सिटी की ओर पेश होने का सुझाव दिया कि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और वह निर्देशों पर सहमति हो गई है, बशर्ते कि भारत संघ धन प्रदान करता है और चिकित्सा परिषद इसके लिए सहमत होती है। ऊपर बताए अनुसार 21 विशिष्टताएँ है। हम. निर्देश देते है कि विश्वविद्यालय प्रत्येक विशेषज्ञता में एक सीट बनाएगा और इस प्रकार 21 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होगी। और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 149 सीटों से अधिक का प्रतिनिधित्व करता 75 प्रतिशत कोटा। सीटों की इस बढ़ी

हुई संख्या के लिए 25 प्रतिशत अखिल भारतीय चयन का आरक्षण लागू नहीं होगा।"

फ्रेशर्स के लिए बनाई गई आरक्षित सीटों में से 21 सीटें प्रत्येक विशेषता से एक होने के कारण उसे हटा दिया जाएगा और वरिष्ठों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार कुल 42 सीटें उपलब्ध होंगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वरिष्ठों के लिए वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर भरा जाता है। 21 सीटों के सृजन में भारत संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। भारतीय चिकित्सा परिषद और वहां एच. पी. सिंह बनाम की मंजूरी की आवश्यकता है।परिवर्तन की अनुमति देने के लिए शायद यह भी आवश्यक होगा मार्गदर्शक-छात्र अनुपात। चूंकि यह एक वर्ष के लिए है और वहाँ पुनरावृत्ति की कोई गुंजाइश नहीं होगी और यह उत्पन्न हुआ है

भारत सरकार बिना सुने हमारे आदेश को स्वीकार करेगी इसे समझने की भावना के साथ जोड़ना और आवश्यक बनाना प्रावधान। हम भारतीय चिकित्सा परिषद को भी सुझाव देते हैं आराम से आवश्यक आवास प्रदान करना आवश्यकताएँ। ये जल्दी से किए जा सकते हैं ताकि समय अनुसूची प्रभावित नहीं हो सकती है। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, हमारे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें अनुरोध किया

गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद की मंजूरी से, राज्य को पर्याप्त संख्या में निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

इस संबंध में राज्य में लागू अन्य नियमों के अधीन किसी विशेषता में डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में सभी आवेदकों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त सीटें। हम नहीं जानते कि न केवल एम. एल. एन. मेडिकल कॉलेज में बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी प्रचलित स्थिति को देखते हुए यह कितना संभव होगा। हम नहीं जानते कि इस आधार पर कितनी अतिरिक्त सीटें बनानी होंगी और क्या ऐसा करना बिल्कुल भी संभव है। हम. इसलिए, कोई विशिष्ट निर्देश न दें, लेकिन पूरे राज्य की स्थिति की समीक्षा करने और यह देखने के लिए कि क्या योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगियों को समायोजित करने वाला कोई समाधान निकाला जा सकता है, इसे राज्य सरकार पर छोड़ दें। हालाँकि, इस तरह की कोई भी समीक्षा रिट याचिकाकर्ताओं के ''जूनियर रेजिडेन्ट द्वितीय वर्ष के रूप में प्रशासन के लिए तत्काल विचार के रास्ते में नहीं आनी चाहिए-लागू अन्य नियमों के अधीन। वे पहले से ही डिग्री पाठ्यक्रम का लगभग एक वर्ष खो चुके हैं, हालांकि, संभवतः, (शायद एक को छोड़कर) वे स्नातकोत्तर पाठधक्रमों में अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं जहां उन्हें पहले प्रवेश दिया गया था। इसे ठीक किया जाना बाहिए और जिन लोगों को भर्ती किया गया है, उन्हें खोए हुए समय की भरपाई करने और

यदि संभव हो तो 1991 के अंत तक अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।

ऊपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं देते है। अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती नीति वर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।